स्वदेश, भोपाल 16 OCT 2011

संपादकीय

बेटियों का हक

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटी बचाओ अभियान का समाज में सकारात्मक सन्देश जाएगा । मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से कन्याओं के पूजन का पावन महोत्सव लोगों को बेटियों के अधिकार को सुरक्षित रखने की प्रेरणा देगा । देश में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात में भारी अंतर के बावजूद इस सम्बन्ध में लोग जागरूक नहीं हैं । वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में शून्य से छह वर्ष आयु वर्ग के 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या केवल 914 है । मध्यप्रदेश में यह अनुपात 912 है। लड़कियों की घटती आबादी से भारी असंतुलन की स्थिति बनेगी । एक अनुमान के अनुसार सन 2050 तक भारत में ढाई करोड़ पुरुषों का विवाह महिलाओं की कमी के कारण नहीं हो सकेगा । जाहिर है, इससे ज़बरदस्त सामाजिक असंतोष की स्थिति पैदा होगी । इस चिंताजनक स्थिति के बावजूद सुधार की दिशा में पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं । लिहाज़ा , राज्य सरकार द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर बेटियों को बचाने का अभियान छेड़ने से स्थिति में बदलाव की आशा की जा सकती है । संतोष का विषय है कि शिवराज सिंह चौहान लम्बे समय से बेटियों के कल्याण की दिशा में सक्रिय है । उन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने के बाद अपने क्षेत्र में हर साल बड़ी संख्या में कन्याओं का विवाह करने का पवित्र काम हाथ में लिया था । राज्य की सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद उन्होंने कन्या दान योजना के तहत बेटियों के विवाह में सरकार का योगदान सुनिश्चित किया है । लाडली लक्ष्मी योजना ने हज़ारों बेटियों का भविष्य सुरक्षित कर दिया है । इस तरह की योजनाएं देश भर में शुरू की जानी चाहिए । वैसे , सामाजिक सुधार के कार्यक्रमों में सरकारों के साथ समाज की मुख्य भूमिका होनी चाहिए । बेटियों की घटती संख्या हमारे देश में औरतों के साथ हर स्तर पर हो रहे भेदभाव , अन्याय और निर्मम शोषण का नतीजा है । बेटियों को लक्ष्मी और दुर्गा की उपमा देने वाला भारतीय समाज उनके साथ कदम-कदम पर अत्याचार करता है । हालत यह है कि पैदा होने से पहले ही बेटियों की गर्भ में हत्या कर दी जाती है । सरकारों ने भ्रूण हत्या रोकने के लिए कठोर कानून बनाए हैं । फिर भी लोग बेटों की चाह में कन्या को इस दुनिया में ही नहीं आने देना चाहते हैं । कन्या के साथ परिवार में ही पक्षपात शुरू होता है । पुत्र की तुलना में पुत्री को खान-पान , शिक्षा और अन्य सभी क्षेत्रों में भेदभाव झेलना पड़ता है । अन्याय का यह चक्र घर के बाहर भी चलता है। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण देने के विधेयक का सालों से लटके रहना इसका प्रमाण है । इन सब विषमताओं को दूर करने के लिए सामाजिक क्रान्ति की ज़रुरत है। क्यों नहीं हमारे सामाजिक , धार्मिक , स्वयसेवी संगठन बेटियों को उनका हक दिलाने के लिए अभियान छेड़ते हैं । बेटियों की घटती आबादी देश को विनाश की कगार पर धकेलने में सक्षम है।

पुत्र की तुलना में पुत्री को खान-पान , शिक्षा और अन्य सभी क्षेत्रों में भेदभाव झेलना पड़ता है । अन्याय का यह चक्र घर के बाहर भी चलता है। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण देने के विधेयक का सालों से लटके रहना इसका प्रमाण है ।